poke me People know what's best for them, not armchair schemes imposed from above

Adarsh Milligram Yojana

The Economic Times. 11-7-15

Tathagata Satpathy

The Narendra Modi government, within its first year in office, has launched a plethora of schemes, hailed by the social media. The common goal is 'development,' a vague term with no clarity as to its meaning or who the beneficiaries are.

I will illustrate why this 'development' model is flawed by picking up one scheme: the Sansad Adarsh Gram Yojana (SAGY).

SAGY has two key objectives: develop a model village through the implementation or convergence process of existing schemes and use of MPLAD funds; and create model villages that can be replicated. A member of Parliament can select any gram panchayat, other than her own native village, which can be developed as an 'adarsh gram' (model village).

The idea is great and it looks good on paper, but its implementation is flawed. My constituency, Dhenkanal, consists of two districts, Dhenkanal and Angul, which together have 2,927 villages. As per SAGY guidelines, I have to pick eight villages and develop them by 2024. Picking eight out of nearly 3,000 villages is a task I am not, repeat not, looking forward to.

Let me be totally selfish and opportunistic here. I am a four-time Lok Sabha member of Parliament. When I seek votes in future elections, people of the vast majority of villages would ask me why did I not choose their village for SAGY, and what makes me competent to beg for their support! It is also possible that supporters of opponents could ask me to scoot and ask for votes only in those handful of villages that I would be insensible enough to earmark for 'development' under SAGY. I have, by the way, received more than 600 applications from villagers (including letters from IFS and IAS officers) requesting that I adopt their village.

No thought has gone in to create any benchmark to make a village eligible for SAGY. Trying to reach that acceptability level could have created competition and better people's participation in improving rural conditions. Why not set criteria—such as no case of harassment of brides or women; outstanding performance by the local school; award for protecting local forest/environment/water bodies; no group clashes within and amongst villagers in last five years; social service activity, etc — which could have set off a race to excel? That has not been done.

Spreading Funds Thin

There has been no separate fund allocation for this scheme. An MP has to use MPLAD funds, which are to the tune of ₹5 crore a year, and use existing central schemes to create an adarsh gram. As a sitting legislator, I already have planned out how to spend the funds. I have allocated funds for solar-powered water pumps, irrigation facilities, transformers, water harvesting structures and parks with a rest shed fringed by fruit-bearing trees to be planted and protected by willing families of the village.

Apart from my dream schemes, there are many panchayats that have demanded funds for other small projects that they need. The ₹5-crore amount may sound huge to a novice. When distributed in seven assembly segments, it barely comes to a little over ₹71 lakh per segment. With today's costs, a project of less than ₹10 lakh is minuscule.

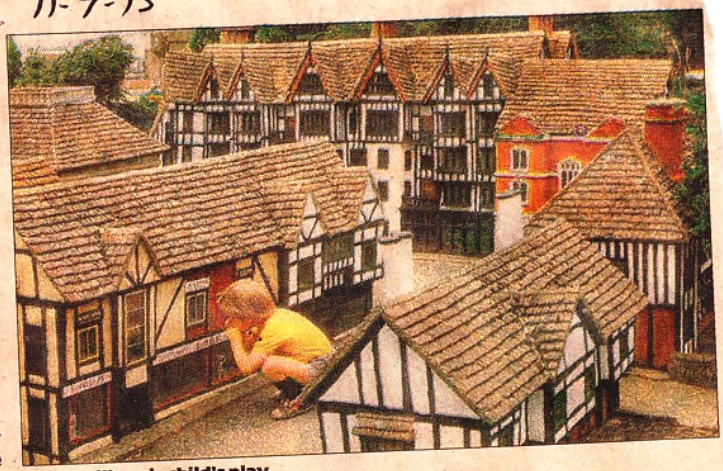

Model village is child's play

Let me illustrate with a parallel example. Every year, an MP gets to recommend few students for admission to Kendriya Vidyalayas. I get hundreds of applications every year and I have to do the Herculean task of selecting only six. This year, after I had selected the candidates based on who had registered earlier chronologically, a young woman came to me with her six-year-old son and asked, "What has this child done to you? Why didn't you give him a seat?" I wonder why a legislator is compelled to get involved in school admissions.

The situation is similar for SAGY, where not one lady but whole villages will come and ask what wrong they had done not to be chosen by me.

The larger issue with this scheme is the assumption that if a model village is created, it would be easy to replicate it in other villages. It is a dangerous assumption. This is where the basic principles of 'development' followed by this government come into focus. Real long-term development takes place if it comes from the people, not by imposing it on them.

Paternalistic Approach

If the people of a village themselves want changes in their vicinity, they make efforts to achieve their goals. They go to the panchayat, give requests to the Collector, MLA and MP. Sometimes together and sometimes not, we try to make interventions to help them in their specific demands.

The SAGY is not a demand-based scheme. It is purely an imposition. It is wrong to assume that an elected representative will know the correct way to improve the standards of living of some 5,000 people who are supposed to be the direct beneficiaries of this scheme.

To reassert, only the people themselves know what they want, politicians and officials must not dictate.

The writer is chief whip in the Lok Sabha, Biju Janata Dal

आर्याना के द्वार पर मोदी की दस्तक

दैनिक भास्कर, 11-7-15

• संदर्भ- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य एशिया के पांच गणतंत्रों की यात्रा

वेदप्रताप वैदिक

भारतीय विदेश नीति परिषद के अध्यक्ष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्तमान विदेश यात्रा अब तक हुई उनकी सभी विदेश यात्राओं से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे अपने पहले साल में ही अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और फ्रांस जैसे शक्तिशाली राष्ट्रों में हो आए। वे यात्राएं सार्थक रहीं, जैसी कि प्रायः रहती ही हैं, लेकिन मेरी याददाश्त में वे ऐसे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं; जो मध्य एशिया के पांचों गणतंत्रों-कजाकिस्तान, उजबेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किरगिजिस्तान और ताजिकिस्तान में एक साथ जा रहे हैं। हमारे कई प्रधानमंत्रियों और विदेश मंत्रियों को इन देशों के नाम भी नहीं मालूम होते थे। ये पांचों राष्ट्र सोवियत संघ के प्रांत थे। जब सोवियत संघ बिखरा तो ये देश आजाद हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने इन सब देशों में जाना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि एक तो ये बहुत पिछड़े थे, दूसरा इन तक पहुंचने के लिए कोई सीधा थल-मार्ग न तब उपलब्ध था और न अब है, तीसरा, हम रूसियों को नाराज नहीं करना चाहते थे और चौथा, अमेरिका और चीन, रूस द्वारा खाली की गई इस जगह को भरने के लिए बेताब थे। उस समय भारत इन अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं के पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था।

मैं हमारे नए विदेश सचिव जयशंकर को शाबाशी देता हूं कि वे अपना ध्यान इस इलाके पर केंद्रित कर रहे हैं। मोदी की यह यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है कि यह क्षेत्र दुनिया का सबसे मालदार क्षेत्र है और लगभग अनछुआ है। यहां इतना तेल, लोहा, गैस, सोना, तांबा और कीमती खनिज हैं कि पूरे दक्षिण एशिया की सैकड़ों वर्षों तक जरूरत पूरी कर सकते हैं। कुछ देश ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल भारत से भी बड़ा है और उनकी आबादी हमारे किन्हीं दो-तीन जिलों के बराबर है। यदि इन देशों में भारत सक्रिय हो जाए तो उसे रूस, चीन और अमेरिका से भी ज्यादा सफलता मिलेगी। भारत के लाखों युवकों को तुरंत रोजगार मुहैया हो सकेगा। अन्य महाशक्तियों के मुकाबले मध्य एशिया में भारत की सफलता की संभावनाएं इसलिए अधिक है कि इस क्षेत्र के लोगों और भारत के लोगों की संस्कृति मूल रूप से एक ही है। मैं पिछले 50 वर्षों से इन गणतंत्रों का अध्ययन करता रहा हूं और वहां कई बार जाकर रहा भी हूं। मैं मानता हूं कि इसके छह करोड़ निवासियों के दिल के करीब जितना भारत है, दुनिया का कोई देश नहीं है। हालांकि इन गणतंत्रों के लगभग सभी निवासी इस्लाम को मानते हैं, लेकिन उनका इस्लाम बिल्कुल सतही है, क्योंकि रूस के कम्युनिस्ट शासकों ने उन्हें इतना दबाकर रखा था कि वे मजहबी पहचान लगभग खो चुके थे। इसके बावजूद उनकी सांस्कृतिक पहचान बराबर कायम रही, जो उन्हें भारत से जोड़ती है। वे अपने आपको आर्यवंशीय मानते हैं। उनकी भाषा, भूषा, भोजन आदि पर आर्यों का गहरा प्रभाव है। कुछ जर्मन विद्वान तो यह मानते हैं कि रूसी इलाके से आए हुए आर्यों ने भारत को बसाया है, जबकि भारत के शास्त्रीय प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि आर्य लोग, संस्कृत भाषा और बौद्ध धर्म इसी क्षेत्र से दुनिया में फैले। मोदी ने अपने भाषणों में इसी भारतीय विरासत का आह्वान किया है।

मध्य एशिया के लोग रूस से आजाद तो हुए, लेकिन वे रूस, चीन और अमेरिका की नई प्रतिस्पर्धा में फंस गए थे। इसी प्रतिस्पर्धा को अब वे शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने वाले नए सदस्यों- भारत और पाकिस्तान की प्रतिस्पर्द्धा के रूप में देखेंगे। इस संगठन में अमेरिका नहीं है, लेकिन रूस और चीन, दोनों है। इन दो परमाणु शक्तियों के साथ अब दो परमाणु शक्तियां और जुड़ने वाली हैं। भारत और पाकिस्तान। सारे विश्व में शायद ही कोई दूसरा क्षेत्रीय संगठन ऐसा है, जिसमें चार-चार परमाणु संपन्न देश हों। इसमें ताजिकिस्तान के अलावा शेष चारों मध्य एशियाई गणतंत्र भी हैं। इन गणतंत्रों के लोग इस्लामी कट्टरवाद के खिलाफ हैं। उन्हें 'इस्लामी राज्य' के कुप्रभाव से बचाना इस संगठन की जिम्मेदारी है। पता नहीं, अब इस संगठन का भविष्य कैसा होगा? यदि पाकिस्तान चाहे तो इसे बहुत उपयोगी बना सकता है। यदि वह चाहे तो भारत के लिए अपने थल-मार्ग खोल सकता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान होता हुआ भारत यदि मध्य एशिया तक सीधा पहुंचने लगे तो सारे दक्षिण एशिया की किस्मत चमक उठेगी। वैसे भारत ने ईरान-अफगान सीमा पर जरंज-दिलाराम सड़क बना दी है। फारस की खाड़ी से अफगानिस्तान होते हुए अब भारत थल-मार्ग से मध्य-एशिया सीधे पहुंच सकता है। अब वह पाकिस्तान पर निर्भर नहीं है, लेकिन यह रास्ता काफी लंबा है। शंघाई संगठन इस लंबाई को कम कर सके तो क्या कहने? दक्षेस में जैसे भारत और पाकिस्तान एक-दूसरे से खिंचे रहते हैं, वैसे ही वे इस संगठन में भी खींच-तान करते रहे तो वे इसका भी भट्ठा बिठा देंगे। नरेंद्र मोदी ने बड़ी हिम्मत की। उन्होंने नवाज शरीफ से मिलने की पहल की। यह भूल-सुधार काबिल-ए-तारीफ है। उन्होंने ही बात तोड़ी थी। अब उन्होंने ही जोड़ी है। दोनों की मुलाकात से अब टूटा तार जुड़ गया है। कई छोटे-मोटे मुद्दों पर सहमति हुई है। यदि दोनों राष्ट्र मध्य एशिया के बारे में सहयोग का रवैया बना लें तो पाकिस्तान बैठे-बिठाए मालामाल हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं कि दक्षेस का विस्तार हो। उसमें मध्य एशिया के पांचों गणतंत्रों, ईरान, बर्मा और मॉरिशस को भी जोड़ा जाए। यदि इन सभी राष्ट्रों का हम साझा बाजार, साझा परिवार, साझा महासंघ खड़ा कर सकें तो वह यूरोपीय संघ से भी ज्यादा शक्तिशाली और संपन्न क्षेत्र बन सकता है। यदि सारे राष्ट्र स्वीकार करें तो इसे 'आर्याना' भी कह सकते हैं। अफगानिस्तान का प्राचीन नाम यही है।

'एससीओ' और 'ब्रिक्स' के बहाने मोदी की भेंट चीन और रूस के राष्ट्रपतियों से भी हो गई। ईरानी और अफगान नेताओं से भी हुई। जाहिर है कि ऐसा अवसर पिछले एक वर्ष में पहली बार आया। मोदी ने इसका इस्तेमाल जमकर किया है, लेकिन चीन अपनी बात पर अड़ा हुआ है। वह लखवी के मामले में अब भी पाकिस्तान के साथ है। अमेरिकी वापसी की वेला में अफगानिस्तान का भविष्य क्या होगा, इस मुद्दे पर भी कोई आशाजनक बात नहीं हुई है। ईरान और रूस के विरुद्ध लगे अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का समाधान खोजने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय नीति-निर्माताओं को यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि इस 'बृहत्तर दक्षेस' की सुरक्षा और संपन्नता की जिम्मेदारी आखिरकार भारत को संभालनी है। भारत की संस्कृति और भारत का लोकतंत्र सारे एशियाई राष्ट्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत की अर्थव्यवस्था का भविष्य भी उज्ज्वल है। यदि भारत की विदेश नीति अपने अड़ोस-पड़ोस को ठीक से साध सकी तो विश्व-शक्तियां उसके आगे अपने आप नत-मस्तक होंगी। मोदी ने 'आर्याना' के द्वार पर दस्तक तो दे दी है, लेकिन भारत के लिए वे तभी खुलेंगे, जबकि हम दूरदृष्टि और धैर्य से काम लेंगे।

dr.vaidik@gmail.com

मोदी की यह यात्रा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस क्षेत्र में इतना तेल, लोहा, गैस, सोना, तांबा और कीमती खनिज हैं कि पूरे दक्षिण एशिया की सैकड़ों वर्षों तक जरूरत पूरी कर सकते हैं।

भारत ने ईरान-अफगान सीमा पर जरंज-दिलाराम सड़क बना दी है। फारस की खाड़ी से अफगानिस्तान होते हुए अब भारत थल-मार्ग से मध्य-एशिया सीधे पहुंच सकता है। अब वह पाकिस्तान पर निर्भर नहीं हैं।

यदि इन सभी राष्ट्रों का हम साझा बाजार, साझा परिवार, साझा महासंघ खड़ा कर सकें तो वह यूरोपीय संघ से भी ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। यदि सारे राष्ट्र स्वीकार करें तो इसे 'आर्याना' भी कह सकते हैं।